*भारतीय अर्थव्यवस्था: अवसर और चुनौतियां**

माइकल देवब्रत पात्र

मैं नोमुरा के 40वें सेंट्रल बैंकर्स सेमिनार में आमंत्रित होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यहां चल रही चर्चाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में चल रहे बड़े बदलावों के संदर्भ में सामयिक प्रासंगिकता ग्रहण करती हैं जो केंद्रीय बैंकिंग के संचालन के लिए नई चुनौतियां पेश करती हैं। अलग-अलग विकास मार्गों और अवस्फीति की अलग-अलग गति और परिमाण के अलावा, शासन परिवर्तन की अपनी अलग अनिश्चितता है।

क्रिकेट के खेल की भाषा में, जिसके साथ भारत को काफी जोड़कर देखा जाता है और यह बेसबॉल के खेल के बारे में भी सच है, बल्ले के ब्लेड के बीच में एक जगह होती है जिसमें लाग्ने के बाद गेंद बल्लेबाज के हाथों में अधिकतम गति और न्यूनतम कंपन के साथ पलटती है और आमतौर पर पूरे मैदान से निकाल जाती है या उसे पार जाती है। इसे स्वीट स्पॉट कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास के दौर में स्वीट स्पॉट पर है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक जीडीपी सबसे तेज गति से बढ़ रही है। मुद्रास्फीति अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है, भले ही असमान रूप से। बाह्य तुलन पत्र पहले से कहीं अधिक मजबूत है, जो तेजी से पूंजी प्रवाह, एक मामूली चालू खाता घाटा और बड़े विदेशी मुद्रा भंडार से मजबूत है। महामारी के बाद राजकोषीय समेकन लगातार तीसरे वर्ष में है। कॉर्पोरेट क्षेत्र ने लीवरेज कम कर दिया है और पूंजी निवेश का एक नया चक्र शुरू करने के लिए तैयार है। वित्तीय क्षेत्र मजबूत और अधिक लचीला है, क्योंकि यह अगले कुछ दशकों में बढ़ते विकास पथ की संसाधन आवश्यकताओं को मध्यस्थ करने के लिए तैयार करता है। इन घटनाक्रमों को दर्शाते हुए, वित्तीय बाजारों को मजबूत आशावाद के साथ प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि निवेशक पहले से ही भारत की कथा में खरीदने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, मैंने सोचा कि मैं आपके सामने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के कुछ पहलुओं, कुछ रोमांचक अवसर और भारत के आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के लिए मुख्य चुनौतियां को प्रस्तुत करूंगा। समय के हित में, मैं गणनात्मक के बजाय चयनात्मक रहूंगा। उदाहरण के लिए, मैं उस परिवर्तनकारी सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करूंगा जो 2005 और 2021 के बीच 415 मिलियन (अमेरिका और जापान की संयुक्त आबादी) को गरीबी से बाहर निकालने में हो रहा है, या विश्व नेतृत्व भारत ने पहले ही विभिन्न कृषि वस्तुओं से लेकर ट्रैक्टरों और स्मार्टफोन से लेकर आईटी सेवाओं तक एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन में प्राप्त कर लिया है, डिजिटल भुगतान और उपग्रह प्रक्षेपण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत की विकास प्रवृत्ति महामारी के बाद के बदलाव के कगार पर है, कोविड-19 से पहले 2000 के दशक के दौरान इसके 7 प्रतिशत से ऊपर बढ़ने के शुरुआती संकेत हैं। हालांकि निजी खपत आमतौर पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत है, यह निवेश और निर्यात है जो महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान करते हैं। 2021-24 की अवधि में, निर्यात लीवर को वैश्विक हेडविंड द्वारा मौन कर दिया गया है, लेकिन बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक व्यय विकास की प्रवृत्ति में स्टेप-अप के लोकोमोटिव के रूप में ले रहा है। हाल के सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि निजी निवेश में भीड़ हो रही है।

भारत के हालिया विकास प्रदर्शन ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया है, जिससे उन्नयन की झड़ी लग गई है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने अप्रैल 2023 और जनवरी 2024 के बीच 2023 के लिए अपने पूर्वानुमान को 80 आधार अंकों से संशोधित किया है। अपने नवीनतम अपडेट में, यह उम्मीद करता है कि भारत वैश्विक विकास में 16 प्रतिशत का योगदान करेगा, बाजार विनिमय दरों के मामले में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, जिसके द्वारा मीट्रिक, भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आगामी दशक के भीतर जर्मनी और जापान से आगे निकलने की स्थिति में है। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ओईसीडी के दिसंबर 2023 के अपडेट के अनुसार, भारत पीपीपी के मामले में

* माइकल देवव्रत पात्र, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण - 25 मार्च, 2024 - क्योटो, जापान में नोमुरा के 40वें सेंट्रल बैंकर्स सेमिनार में।

2045 तक अमेरिका से आगे निकलकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह अंतर्निहित ताकत भारतीय रुपये (₹) के पीपीपी मूल्य में भी दिखाई देगी.

अवसर

इस सेटिंग में, मुझे कुछ टेलविंड का हवाला देना चाहिए जो संभवतः भारत के टेक-ऑफ को शक्ति प्रदान करेंगे।

सबसे पहले, जनसांख्यिकी विकास की बढ़ती प्रोफ़ाइल का पक्ष लेती है। वर्तमान में, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे कम उम्र है। औसत आयु लगभग 28 वर्ष है; 2050 के दशक के मध्य तक उम्र बढ़ने तक नहीं। इस प्रकार, भारत को तीन दशकों से अधिक की जनसांख्यिकीय लाभांश खिड़की का आनंद मिलेगा, जो बढ़ती कामकाजी उम्र की जनसंख्या दर और श्रम बल भागीदारी दर से प्रेरित है। यह दुनिया के समक्ष व्यापक रूप से उपस्थित बढ़ती उम्र की समस्या के ठीक विपरीत है।

दूसरा, भारत का विकास प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से घरेलू संसाधनों पर आधारित रहा है, जिसमें विदेशी बचत एक छोटी और पूरक भूमिका निभाती है। वास्तव में, भारत घरेलू बचत और निवेश दरों के बीच उच्च सहसंबंध की पहेली को सहन करता है जिसे मार्टिन फेल्डस्टीन और चार्ल्स होरियोका ने 1980 में देखा था। यह चालू खाता घाटे (सीएडी) में भी परिलक्षित होता है जो सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 25 प्रतिशत की वहनीय सीमा के भीतर रहता है। वर्तमान में, सीएडी का औसत लगभग 1 प्रतिशत है और यह बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन के विभिन्न संकेतकों से जुड़ा हुआ है – उदाहरण के लिए, बाहरी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम है और शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश देनदारियां 12 प्रतिशत से कम हैं। ऋण सर्विसिंग वर्तमान प्राप्तियों के 7 प्रतिशत से कम को अवशोषित करती है, जिसमें 12 महीनों से अधिक के कारण मूल पुनर्भुगतान अंतरराष्ट्रीय भंडार के 48 प्रतिशत से कम है। इन जन्मजात शक्तियों को दर्शाते हुए, आईएनआर 2023 में सबसे कम अस्थिर मुद्राओं में से एक रहा है; वास्तव में, यह 2024 के शुरुआती भाग के दौरान नाममात्र और वास्तविक दोनों शब्दों में सराहना कर रहा है।

तीसरा, एक बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन के माध्यम से कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया ने 2020 में सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 13.1 प्रतिशत और सार्वजनिक ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 89.3 प्रतिशत तक पहुंचा दिया। 2021-22 की शुरुआत में राजकोषीय समेकन का एक क्रमिक मार्ग अपनाया गया जिसने मार्च 2024 तक सामान्य सरकारी घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 8.6 प्रतिशत और सार्वजनिक ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 81.6 प्रतिशत तक ला दिया है। एक गतिशील स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम (डीएसजीई) मॉडल को नियोजित करते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादक रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को लक्षित करके, ऊर्जा-कुशल संक्रमण को गले लगाने और डिजिटलीकरण में निवेश करके राजकोषीय खर्च को फिर से प्राथमिकता देने से 2030-31 तक सामान्य सरकारी ऋण में जीडीपी के 73.4 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत, आईएमएफ द्वारा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए ऋण-जीडीपी अनुपात 2028 में बढ़कर 116.3 प्रतिशत और उभरते और मध्यम आय वाले देशों के लिए 75.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

चौथा, भारत का वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से बैंक आधारित है। 2015-2016 में, वैश्विक वित्तीय संकट और आने वाले वर्षों के मद्देनजर परिसंपत्ति हानि के ओवरहांग को परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के रूप में एक गहरी सर्जरी के माध्यम से संबोधित किया गया था। 2017-2022 के दौरान बड़े पैमाने पर पुनर्पूंजीकरण किया गया था। लाभकारी प्रभाव 2018 से दिखाई देने लगे – मार्च 2023 तक सकल और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 1 प्रतिशत हो गया, जिसमें बड़े पूंजी बफर और तरलता कवरेज अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था। एक दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) ने बैंकों की बैलेंस शीट में तनाव को दूर करने के लिए संस्थागत वातावरण बनाया है। ऑन-साइट पर्यवेक्षण ऑफ-साइट निगरानी के साथ पूरक है, जो सुपरटेक, बड़े डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा अभ्यास का उपयोग करता है। हाल ही में, बैंक लाभप्रदता में मजबूत सुधार के साथ-साथ एक पुण्य क्रेडिट उछाल ने जड़ पकड़ ली है। क्रेडिट जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए तनाव परीक्षणों से पता चलता है कि गंभीर तनाव परिदृश्यों के तहत भी बैंक न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से ऊपर रहेंगे। मैक्रोइकॉनॉमिक और वित्तीय स्थिरता मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए आधार प्रदान कर रही है।

पांचवां, भारत प्रौद्योगिकी पर एक परिवर्तनकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जेएएम की त्रिमूर्ति - जन धन (मूल नो-फ्रिल खाते); आधार (सार्वभौमिक अद्वितीय पहचान); और मोबाइल फोन कनेक्शन - औपचारिक वित्त के दायरे का विस्तार कर रहा है, तकनीकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा दे रहा है और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लक्ष्यीकरण को सक्षम कर रहा है। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), एक ओपन-एंडेड सिस्टम है जो किसी भी भाग लेने वाले बैंक के एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों को अधिकार देता है, इंटर-बैंक, पीयर-टू-पीयर और व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा रहा है। भारत में भुगतान प्रणाली 24 बाय 7 बाय 365 आधार पर संचालित होती है। ऑफलाइन भुगतान, फीचर फोन भुगतान और संवादात्मक भुगतान जैसी कार्यक्षमताओं को शामिल किया गया है। यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

छठा, भारत में मुद्रास्फीति, महामारी से कई और अतिव्यापी आपूर्ति झटके, मौसम से प्रेरित खाद्य मूल्य स्पाइक, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कमोडिटी मूल्य दबावों के बाद बढ़ रही है। विशेष रूप से, हालांकि, भारत में मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति की उम्मीदों को रोकने और मूर्खतापूर्ण खाद्य मूल्य दबावों को समाप्त करने के लिए समन्वित मौद्रिक-राजकोषीय नीतियों के जवाब में जल्दी चरम पर पहुंच गई। इसके परिणामस्वरूप, सितंबर 2023 से मुद्रास्फीति सहिष्णुता बैंड में वापस आ गई है, जिसमें मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य से भी कम हो रही है. समन्वित दृष्टिकोण ने आरबीआई को खाद्य मूल्य झटके के पहले दौर के प्रभावों को देखने की अनुमति दी ताकि आपूर्ति प्रबंधन मांग के साथ आपूर्ति को संतुलित कर सके। इसने मौद्रिक नीति को सख्त करने की वित्तीय स्थिरता और विकास जोखिमों को कम किया।

चुनौतियां

भारत महामारी से डरा हुआ लेकिन लचीला है और इन अवसरों को पैदा कर रहे थर्मल की सवारी करके अपनी विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं के साथ एक प्रयास करने के लिए तैयार है। टेक-ऑफ को कई चुनौतियों से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों से जूझना होगा। मैं पुन समय के हित में चयनात्मक होने का प्रस्ताव करता हूं।

जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना जीडीपी वृद्धि में कार्यबल के योगदान का विस्तार करने के आसपास टिका है। वर्तमान में, भारत में मूल्य वर्धित के लिए श्रम का योगदान क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य में खराब है – एक विशिष्ट नौकरी के लिए उपयुक्त कौशल के संदर्भ में, केवल 51 प्रतिशत रोजगार योग्य है, जो कौशल मिशन की महत्वपूर्णता को उजागर करता है जो कौशल अंतर को पाटने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से चल रहे हैं। स्टार्टअप और उद्यमिता सहायता पहल नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन रोजगार के नए रास्ते खोलता है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण योजनाएं भी मूल्य वर्धित में श्रम के योगदान को बढ़ावा देती हैं। 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसका मैं शीघ्र ही उल्लेख करूंगा। इसके अलावा, कार्यबल [1] में महिलाओं की भागीदारी में भारत कम स्थान पर है। कामकाजी महिलाओं के पक्ष में सामाजिक मानदंडों की आवश्यकता के लिए महिला श्रम भागीदारी बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती है; शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों में विविधता को प्रोत्साहित करना; कार्यस्थलों पर लचीले काम के घंटे और महिलाओं के अनुकूल नीतियां और सुविधाएं; और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना - मेटावर्स [2] रोमांचक अवसर प्रदान कर सकता है।

एक योग्य श्रम शक्ति उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित होने पर सबसे अच्छा योगदान देती है। विश्व स्तरीय मानकों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को 2015 में स्थिर 2015 डॉलर में 90.6 अमेरिकी डॉलर पर भारत के प्रति व्यक्ति निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए पारदर्शी नियमों, तेजी से मंजूरी, सुचारू भूमि अधिग्रहण और जलवायु मंजूरी नीतियों और पर्याप्त वित्त की आवश्यकता होगी। लगातार केंद्रीय बजटों में निरंतर बुनियादी ढांचे के खर्च और रसद धक्का

[1] विश्व बैंक (विश्व विकास संकेतक) के अनुसार, वर्ष 2022 में महिला श्रम बल भागीदारी दर के मामले में भारत 186 देशों में 170वें स्थान पर है।

[2] मेटावर्स आभासी दुनिया को संदर्भित करता है जिसमें अवतार द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उपयोगकर्त्ता आमतौर पर 3D में बातचीत करते हैं, जो आभासी वास्तविकता (वीआर), संवर्धित वास्तविकता (एआर) हेडसेट और ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग से सुगम होता है।

भारत के बुनियादी ढांचे के लक्ष्य के वित्तपोषण के लिए वातावरण बना रहा है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और पीएम गति-शक्ति मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण सार्वजनिक नीति का एक प्रमुख फोकस रहा है, जो 2015-16 के बाद कुल निवेश में सार्वजनिक निवेश के हिस्से में उछाल से पूरित है। उप-राष्ट्रीय सरकारों और निजी क्षेत्र को भी पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया है। बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, डिजिटल बुनियादी ढांचा और रूफटॉप सोलराइजेशन शामिल हैं।

भारत के भविष्य में कार्यबल की भूमिका का विस्तार करने का सार नौकरियों के औपचारिकरण में निहित है, जो विनिर्माण क्षेत्र की भूमिका को केंद्र में लाता है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में विनिर्माण को काफी हद तक दरकिनार कर दिया - सेवा क्षेत्र आज भारत की अर्थव्यवस्था का दो-तिहाई हिस्सा है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भारत का विनिर्माण क्षेत्र (2015 के अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में) विश्व औसत से बहुत नीचे है। 1990 के दशक से विनिर्माण क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 7 प्रतिशत [3] रही है। 8.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, 2030-31 तक जीवीए में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगी, और यदि विकास दर को 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है तो यह 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा – जिससे भारत अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। इसे प्राप्त करने के लिए, भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति (स्वचालन; डेटा विनिमय; साइबर-भौतिक प्रणाली, चीजों का इंटरनेट; क्लाउड कंप्यूटिंग; संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग और स्मार्ट फैक्ट्री, उन्नत रोबोटिक्स) के अनुकूल होना चाहिए। एक कुशल श्रम शक्ति कुंजी रखेगी।

भारत के विनिर्माण और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए – दुनिया के लिए भारत में निर्माण। वर्ष 2030 तक भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 768 बिलियन अमरीकी डॉलर या विश्व के कुल निर्यात के 2.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक कुल निर्यात के 5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए गहन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आईटी और डिजिटल सेवाओं, मूल्य वर्धित कृषि उत्पादों जैसे क्षेत्रों के रूप में क्षमता मौजूद है; उच्च मूल्य पर्यटन; वित्तीय सेवाएं; खुदरा और ई-कॉमर्स। वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) पहले से ही बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) को उत्पाद नवाचार का नेतृत्व करने, तकनीकी प्रगति चलाने, अगली पीढ़ी की बौद्धिक संपदा (आईपी) बनाने और वैश्विक स्तर पर डिजिटलीकरण पहल का नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करके इस क्षमता का दोहन कर रहे हैं। भारत अपनी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों जैसी पहलों के माध्यम से इस निर्यात जोर की तैयारी कर रहा है; और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की निर्यात क्षमता का समर्थन करके।

जैसा कि भारत एक मजबूत विनिर्माण आधार द्वारा समर्थित निर्यात पावरहाउस के रूप में उभरता है, एक प्राकृतिक परिणाम भारतीय रुपये का पूर्ण अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा। कई कारक पहले से ही मौजूद हैं। भारतीय डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है और भारत प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता है। भारतीय रुपया तटवर्ती की तुलना में तीन गुना अधिक अपतटीय व्यापार करता है। भारत की एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान व्यवस्था है और भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है। गहरे और तरल वित्तीय बाजार विकसित हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र एक संपन्न वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ वैश्विक वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभर रहा है। वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय सॉवरेन बॉन्ड के आसन्न समावेश से भी भारत में निवेश की मांग बढ़ने की संभावना है। व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर नीतिगत जोर भी भारतीय रुपया के लिए सकारात्मक है। यदि आईएनआर का कारोबार वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार (4 प्रतिशत) में गैर-अमेरिकी गैर-यूरो मुद्राओं के हिस्से के बराबर होता है, तो भारतीय रुपया एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में आ जाएगा।

अंतिम चुनौती जिस पर मैं ध्यान दूंगा वह सतत विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हरा-भरा बनाना है। पार्टियों के सम्मेलन 26 (सीओपी 26) में, 2030 तक पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में शामिल हैं: (i) 500 जीडबल्यू गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता; (ii) 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा समाविष्ट ऊर्जा

[3] विनिर्माण क्षेत्र में इसका मौजूदा हिस्सा 17 प्रतिशत है।

मिश्रण; (iii) कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनों को एक बिलियन टन तक कम करना; (iv) अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना; और (v) 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करना। यह अनुमान लगाया गया है कि शुद्ध शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी तक पर्याप्त पहुंच के साथ-साथ 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता है।

समाप्ति

प्रतिष्ठित ब्रिटिश अर्थशास्त्री, एंगस मैडिसन के अनुसार, जो आर्थिक वृद्धि और विकास के माप और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते थे, भारत 1 से 1000 ईस्वी के दौरान विश्व जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अगले 600 वर्षों में, भारत रुक-रुक कर दूसरे स्थान पर गिर गया, लेकिन 1700 ईस्वी तक विश्व जीडीपी के 24.4 प्रतिशत के हिस्से के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया। उसके बाद औपनिवेशिक शासन और एक लंबा प्रतिगमन आया।

मेरे द्वारा वर्णित जन्मजात शक्तियों और ऊर्जा और परिवर्तन को देखते हुए, जो राष्ट्र को अपनी चुनौतियों पर काबू पाने और अपने आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यह कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में 10 प्रतिशत की विकास दर के साथ आगे बढ़ जाएगा। यदि यह हासिल किया जाता है, तो भारत 2045 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन जाएगा, जैसा कि पहले दिखाया गया है, लेकिन 2032 तक और 2050 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

धन्यवाद।